been submitted to the Railways. We look into them as to which are feasible in terms of our parameters and take further action. I think with these words, I must say that the project Jiribam-Imphal which he was mentioning, was only in lieu of Diphu-Karang project, and it has been taken up. It is more economical in terms of cost as well as the years of completion, clearance etc.

SHRI T. R. ZELIANG: The distance between Jiribam to Imphal is 223 kms. And again Jiribam to Diphu is another 300 kms. So, the entire length of road is more than 500 kms. whereas Diphu to Karong, Imphal is within 200 kms. So, will people prefer to travel *via* Jiribam-Silchar to Diphu-Guwahati, the main line of the country or will people prefer to go through this Nagaland-Karong-Imphal which is 200 kms.? There is a difference of 300 kms. I am talking about that, Sir. That is why I am asking whether you are going to restore all the projects which have taken 20 years to get approval. Now after approval you are talking about Kohima. How long will it take to get approval? You are going to scrap it. This is a very tricky one. *...(Interruptions)...* We can never get it. The Government should reconsider to restore all projects which were already approved *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, would you like to respond?

SHRI R. VELU: This has got a different angle about roads and other things. This will be examined and further action will be taken if it is feasible. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has told that he will examine it. Next question.

Points arising out of the answer given in the Rajya Sabha on 17th February, 2006 to Unstarred Question No. 38 regarding "Pollution in Ganga"

श्री उपसभापति : श्री कमाल अख्तर। आज जरा प्रिसाइस बोलिएगा।

श्री कमाल अख्तर (उत्तर प्रदेश) **:** उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि सभी लोगों को जल्दी जाना हैं, लेकिन आज जो सवाल

हमारे सामने हैं, वह करोड़ो लोगों की जिन्दगी से जुडा हुआ सवाल हैं, साथ ही साथ हिन्दुस्तान के अन्दर रहने वाले करोड़ो लोगों की धार्मिक भावनाओं से भी जुडा हुआ यह सवाल हैं। मैं जानता हूं कि समय कम है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि सवाल को उठाने के लिए आप मुझे पूरा समय देंगे।

उपसभापति जी, आपने करोड़ो लोगों की भावनाओं, स्वस्थ्य, रोजगार एवं जीवन देने वाले विषय पर चर्चा स्वीकार करके जो मुझे समय दिया हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इस देश जीवन के लिए नदिंया बहुत महत्वपूर्ण हैं। गंगा, यमुना, सतजलुज, सरस्वती, रामगंगा इत्यादि ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो हिन्दुस्तान का गौरव हैं साथ ही इनसे देश के करोड़ो लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यें करोड़ लोगों को रोजगार देने का भी काम करती हैं, करोड़ों लोगों का जीवन इन्हीं नदियों से जुडा हुआ हैं। चाहे कोई भी सरकार रही हो, हर सरकार नदियों को प्रदुषण से बचाने के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलाई हैं और इन पर अरबों-खरबों रूपया खर्च किया।

मान्यवर, यदि आपने कभी यमुना नदी को देखा हो, जो दिल्ली से होकर गुजरती हैं, वह यमुना नदी आज नदी रह गई हैं, वह एक गंदा नाला हो गई। आज पूरी दिल्ली का कचरा उस नदी के अंदर डाला जाता हैं। उसके दाएं-बाएं इतना अधिक अतिक्रमण हो गया हैं कि जिस यमुना में नहाने के बाद लोग अपने आपको धन्य महसूस करते थे, अपने गुनाहों को माफ करवाने के लिए लोग उसमें जाकर नहाते थे, लेकिन आज यदि कोई आदमी उसमें जाकर नहा ले, तो मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि उसकी कोई न कोई चर्म रोग हो जाएगा।

यहां तक यमुना नदी का संबंध हैं, उसे तो सारी सरकारें एवं अन्य सभी लोग भी मिलकर बचा नहीं सके, लेकिन उपसभापति जी आज सवाल गंगा का हैं। गंगा वह नदी हैं जो हरिद्वार से निकलने के बाद यदि कहीं पर सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है, सबसे पहले जहां उसे प्रदूषित किया जाता हैं, तो वह मेरा क्षेत्र हैं। यदि आपको कभी रास्ते से गुजरते हुए गजरौला या मुरादाबाद जाने का मौका मिला हो, आप वहां जाकर देखिए जब गजरौला आने से 10 किलोमीटर पहले दुर्गन्ध आने लगती हैं, तब वहां से निकलने वाला हर आदमी यह समझ लेता हैं अब गजरौला आ गया इसके कुछ जिम्मेदार फैक्टरीज हैं और वे फैक्टरीज हैं-जुबलेंट आर्गेनिस, रामगंगा फर्टिलाइजर, जे.के. डेरी एंड फूड्स और इसके अलावा वहां कई यूनिटें ऐसी हैं जो वहां पर निकलने वाली एक महत्वपूर्ण बगद नदी के अंदर अपना रासायनिक कचरा डालती हैं और उसको प्रदूषित कर रही हैं। यही नदी आगे जाकर कच्ला घाट के अंदर जो 70 किलोमीटर जाती हैं, उस 70 किलोमीटर के बाद गंगा में जाकर यह नदी गिरती हैं। इस प्रदूषण की सबसे अधिक जिम्मेदार जुबलेंट आर्गेनिस

और रामगंगा फर्टिलाजर हैं। मान्यवर, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं और अपने बड़े यकीन के साथ कहता हूं कि भोपाल जैसा खतरनाक कांड अगर कहीं पर दोबारा दोहराया जाएगा, अगर सरकार नहीं जागी तो मैं आपके माध्यम से, मंत्री जी यहां बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि वह गजरौला के अंदर जे.पी. नगर के अंदर दोहराया जाएगा, क्योकि आज पूरे वातावरण के अंदर इतनी तहर की गैसेज औघोगिक इकाइयों द्वारा छोड़ी जा रही हैं, आप सब लोग जानते हैं कि अमरोहा जो आम की फसल के लिए मशहूर था, परन्तु आज इन फैक्टरीज के प्रदूषण से हजारों, लाखों, करोड़ो रूपए की आम फसलें बर्बाद हो गई। उस क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी आम आदमी की फसल नहीं उगा सकते। उसके 10 किलोमीटर के अंदर उस बगद नदी के बराबर में जो दो सौ गावं पड़ते हैं, उन दो सौ गांवो के अंदर एक गावं भी ऐसा नहीं हैं जहां पर आपको पीने का पानी साफ मिल सके। वहां पर आप जाकर देख लीजिए कि जब गांव के वासी नल चलाते हैं तो रंगीन पानी निकलता हैं, जहरीला पानी निकलता हैं। आज गजरौला क्षेत्र के लोगों के अंदर तरह-तरह के ह्दय रोग, नपुंसकता, आंखों के रोग, चर्म रोग, फेफड़ो की बीमारी ऐसी तमाम बीमारियां इन रासयनिक गैसों की वजह से हो रही हैं तथा वहां पर लोग पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर हैं। उपसभापति महोदय, फैक्टरी से निकालने वाले पानी ने बगद नदी को इतना प्रदूषित कर दिया हें कि उसमें कोई भी जीव-जन्तु जीवित नहीं हैं औंर जहां पर हजारो लोग मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे वे भी बेकार हो गए हैं। आज पूरी नदीं के अंदर आपको पानी के अंदर रहने वाला एक जीव भी निन्दा नहीं मिलेगा। साल के अंदर हजारों मवेशी वहां के जहरीले पानी को पीकर मर जाते हैं। जो किसान उस पानी के अन्दर से होकर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर उनको चर्म रोग हो जाते हैं, कोढ़ जैसे भयानक रोग भी उनको हो जाते हैं। उपसभापति महोदय, सबसे जो खतरानाक चीज हैं वह यह हैं कि इस फैक्टरी का जो प्रबंध तंत्र हैं वह इतना मजबूत हैं कि इस देश की सरकार के ऊपर और मुझे कहना नहीं चाहिए कि सदन के जो आदेश हैं, उनकी अवेहलना तक की जाती हैं। 1997 के अंदर जस्टिस गुमान मल लोढा जी के नेतृत्व में 17 सदस्यों की एक संसदीय उपसमिति बनी और उस समिति ने वहां जाकर प्रदूषण का सर्वे किया, गावं वालों की राय ली, बगद नदी का भी निरीक्षण किया। उपसभापति महोदय, आज प्रबंधन तंत्र के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर जो पानी के नमूने लिए गए उन नमूनों को वहां पर चुरा लिया गया। तो जस्टिस गुमान मल लोढा जी ने वहां कहा कि जिन प्रबंध तंत्र के लोगों ने पानी के नमुने चुराए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन गजरौला क्षेत्र के सी.ओं. की 7 साल की तफ्तीश के बाद आज तक एक भी अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आपको बताना चाहता हूं कि यहीं इसी सदन के अंदर आपको सामने वहां का दूषित पानी हम लोगों ने दिखाया था। माननीय उदय प्रताप जी ने भी इस सदन में इस मामले को उठाया था। लोक सभा के अंदर माननीय राम गोपाल यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद यहां से निर्देश दिया गया जिस पर केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड की टीम भेजी गई तथा फैक्टरी प्रबंधको द्वारा दी

गई रिपोर्ट के आधार पर ही इन अधिकारियों द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार की गई और इस तरह से गलत तथ्यों की रिपोर्ट मंत्रालय द्वारा इस सदन में दी जाती हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि वहां पर ट्रीटमेंट प्लाटं लगा दिए गए हैं। लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट को चलाया नहीं जा रहा हैं और रात को प्रदूषित पानी बगद नदी के अंदर छोड़ दिया जाता हैं। जो ट्रीटमेंट लैगून खोद लिए गए हैं, इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया हैं, उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जाकर देखिए कि इन लैगून का जहरीला पानी, फैक्टरी से निकलने वाला कचरा, आज जमीन के अंदर एब्जॉर्ब किया जा रहा हैं और वहां का जो जल स्तर हैं तथा भूमि के नीचे वाला जल पूरह तरह से दूषित हो गया हैं। आज वहां का प्रबंध तंत्र इतना मजबुत हैं, सरकार के ऊपर इतना मजबूत हैं कि आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब हम लोगों ने गुमान मल लोढा जी कि रिपोर्ट मांगी, उसके ऊपर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी तो आज लायब्रेरी के अंदर समिति की रिपोर्ट नहीं हैं, मंत्रालय के अंदर रिपोर्ट नहीं हैं। उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं, तो गजरौला हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोघ करूंगा कि अगर आपको लाखों लोगों की जान बचानी हैं, लाखों लोगों का जीवन बचाना हैं और हिन्दुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण नदी,जिससे लोगो की धर्मकि भावनाएं जुड़ी हैं,जिससे लोगों के जज्बात हुड़े हुए हैं, उस नदी को प्रदूषण से बचाना हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बार फिर, आप इस सदन की एक संसदीय उप समिति बनाकर इसकी जांच करवाइये अथवा आप किसी ऐसी संस्था से जांच करवायें जिसके अंदर जनप्रतिनिधि हों,जिसके अंदर मानवधिकार की संस्थाएं हों,जिसके अंदर उस क्षेंत्र के जन प्रतिनिधि हों, जिसके अंदर सरकारी कर्मचारी हों। आप कोई ऐसी जांच कमेटी बनायें जिसके माध्यम से वहां की जांच होने के बाद, वहां की जनता को राहत मिल सके और जो फैक्ट्रयों द्वारा जल प्रदूषण फैलाया जा रहा हैं, जो तरह तरह की रासायनिक गैस वहां इकट्ठी की जा रही हैं, उसके कारण आने वाले समय में, होने वाली तबाही से, आज गजरौला को बचाइयेगा। धन्यवाद।

श्री उपसभापति : डा. चन्दन मित्र।

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश) **:** उपसभापति महोदय, मैं ...।

श्री उपसभापति : वह उन्होने बोल दिया हैं, आप समर्थन कर दीजिए।

श्री नन्द किशोर यादव : उपसभापति महोदय, श्री कमाल अख्तर जी ने जो यहां पर सवाल उठाया हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और निश्चित रूप से इस पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री उपसभापति : मैं आपको बाद में बुलाता हूं। डा. चन्दन मित्र।

DR. CHAMDAN MITRA (Nominated). Thank you Mr. Deputy Chairman, Sir. I am really grateful that we are having this debate. The matter has been raised during the Question Hour on Friday and the hon. Minister was also present at that time. So, I am sure, you and other hon. Members of the House are fully aware of the very serious situation prevailing in the holy city of Varanasi which is the holiest spot, I would say, not only for the Hindu community but for the entire country. The situation of Ganga at Varanasi, which has been, from time immemorial, the place where people have come and paid respects not only from all over the country, but all over the world is in a pathetic condition, despite twenty years of the GAP. It is truly, I think, ironic that we are having this discussion just the day after the death anniversary of Shri Rajiv Gandhi who was the initiator of the Ganga Action Plan twenty years ago and raised so much hopes and aspirations of the people of India by undertaking this Plan.

Sir, I speak on this subject with authority of having visited Varanasi to examine the situation on the spot only two months ago as a part of the delegation in which Mr. Tariq Anwar, a fellow Member of this House and the then Member, Mr. Balbir Punj were also there. There were three Member from the Lok Sabha. We went to do on the spot survey of the situation in Varanasi. Sir, the situation is so serious that the river in Varanasi, leave alone the water being fit for drinking, it is not even fit for bathing according to the WHO guidelines. The river is on the verge of dying. The oxygen level in the river has fallen to precarious proportions. The fish are dead. And, if you go by a boat, along the river, you find bubbles rising from methane gas. That happens as a result of the pollution and garbage that is being disposed into the river. Sir, we went on a boat from Varuna to Asi. The city of Varanasi gets its name from these two rivers. Varuna and Asi become as Varanasi. So, these two rivers flank the holy city of Varanasi. When you reach the point where river Varuna discharges into river Ganga, you get a putrid smell, because the entire garbage is coming into the river Ganga. At the other end, the Asi river is no longer a river. It is a pure drain. It is as polluted as Najafgarh drain here in Delhi and other such drains. All this water is flown into the river. Sir, all along the route, sewage pipes discharging water and untreated waste into the river. All this was supposed to have been checked by water treatment plants. Several plants have been built along the way.

But, those plants do not operate. There is no electricity to begin with And, these plants are heavily dependent on electricity and, since there is a power shortage in UP, as in the rest of the country, the plants are inactive most of the time. In fact, at the time of the heaviest sewage disposal in the morning, there is power cut and water comes in untreated and flows into the river.

So, this is for everybody to see. It is no new development. It has been going on for years and no plan has so far been made on how to stop the discharge of absolutely untreated sewage into the river.

Sir, the specific point which I want to make, and on which I would seek the Minister's response is this. There is a plan which was submitted several years ago as a solution to this. The solution is very simple. It is not a very costly solution. The solution was to construct a drain along the *ghats* of Varanasi. Starting from the Asi River to the Varuna River, you go along the *ghats,* and a cover drain was to be constructed so that all the sewage that is flowing into the river could come into this. As you know, the city of Varanasi is at a height from the Ganga. All the sewage water that is coming in should discharge itself into this particular drain and the drain would run along the entire length of the riverfront of Varanasi. It would then be taken by a pipe across the river and be discharged in an uninhabited island in the middle of the river. Now this plan, with Japanese technology, has been there for several years. It is a far less costly plan than what is being proposed by the State Government, that is, to build more sewage treatment plants. Sir, sewage treatment plants have been set up and they have been ineffective. Now, this simple technology which will relieve the problem almost completely, has not been implemented. For seven years a litigation has been going on between the Uttar Pradesh Jal Nigam and the residents of Varanasi, including *the* Varanasi Municipal Corporation which had passed a unanimous resolution approving this plan. Now, according to the Nagar Palika Act, it should be the responsibility of the Varanasi Municipal Corporation to devise a plan, and for the Centre to allocate the funds through the State Government for its implementation. By ignoring the local authorities and not taking the local factors into consideration, this scheme of bringing in more machines, more water disposal plants, sewage disposal plants and consuming power, totally impractical, which will cost a lot of money. We have already seen that this plan is ineffective. I would like to know from the hon. Minister: What

is its status here and why it is not being implemented? We MPs submitted a memorandum when our delegation went there at the invitation of the Sankat Mochan Trust, which is doing a lot of good work there. Mahant Virbhadra Mishraji has been at this for so many years. He still bathes in the river everyday, which, actually, very few people risk doing now. As an hon. Member was saying, like in the Yamuna, if you actually have a holy dip in the Ganga today, you will come out an unholy man because of the rashes that are likely to erupt in your body.'In this situation, given the very serious nature of the crisis and the faith of millions and millions of people that is involved, this matter has to be taken up on a war footing. The Ganga Action Plan phase II for Varanasi has been held up for so many years. Sir, I appeal to the Minister to give urgent consideration so that the Ganga that has become maili is restored to a situation where we can still say''गंगा तेरा पानी अमृत।''

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, this Ganga Action Plan was later renamed as the National River Conservation Plan. It was expected to cost Rs. 3,780 crores, but till March 2006, an expenditure of Rs. 2,500.39 crores reported to have been incurred. Now, Sir, it has just now been mentioned that the plan target of STP, that is, Sewage Treatment Plan, was not achieved. Whatever little was achieved, that also went down due to very poor maintenance. Then, Sir, at the stretch between Kanpur-Allahabad-Kannauj, water quality of Ganges has been monitored. Pollution has been found to be higher than the limit. Due to the existence of a large number of leather and chemical industries, water is being further polluted.

Pollution in the Yamuna River is also a matter of grave concern. The quality of water is below standard in Delhi due to heavy discharge of sewage water. The same is the situation in Agra. It is like a dirty canal. I had an opportunity to visit those places, and I found that the overall progress is poor. Even some of the facilities created like electric crematorium etc., become non-operational shortly after commissioning.

In Allahabad, Haridwar and Kanpur, such crematoriums started in 1991, and stopped operating in 1997, due to non-payment of electricity bills, etc. I remember that once the CAG also made a very serious comment against the Ganga Action Plan. Then, it is found that half-burnt dead bodies are being thrown in the Ganges, because of the non-functioning of the electric

crematorium; and, the people's temperament is also like that. There is lack of scientific temperament. So, that is further polluting the river water. Then, the problem of solid waste management is there. I would like to inform the Minister that even in the Mid-Term Appraisal Report, it has been advocated that an independent evaluation would be useful for such stocktaking, because a very huge amount has been spent. The meaningful coordination between the State Governments and local bodies with active participation of the Ministry of Environment and Forests is necessary. I want a definite answer from the Minister. Thank you.

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : सर, माननीय सदस्य ने देश की प्रमुख नदियों में औघोगिक प्रदूषण,गंगा नदी और बगल में औघोगिक प्रदूषण के बारे में चिंता जाहिर की हैं। इसके साथ अन्य माननीय सदस्यों ने भी वाराणसी में गंगा एक्शन प्लान के तहत कार्य न होने से पानी की क्वालिटी खराब होने की बात कहीं हैं और अन्य सदस्यों ने कानपुर और कन्नौज में स्थिति खराब होने के बारे में जिक्र किया हैं। सर, गंगा की सफाई का अभियान स्वर्गीय राजीव जी ने इस देश में 1985 में प्रारम्भ किया था। गंगा नदी और दूसरी नदियों लोगों की आस्था का केन्द्र रही हैं, जीवन रेखा रही हैं, लोगों को सिचाई का पानी मिलता और पीने का पानी भी मिलता और हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता हैं। जिस प्रकार शरीर में धमनियों में खून बहता हैं, यदि अच्छा खून नहीं हैं तो आदमी अस्वस्थ हो जाएगा, इसी प्रकार सारी नदियों का रोल किसी भी देश में रहता हैं। सर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हू कि जो नदियों के उपयोग हैं, उसके अलावा उनमें किस प्रकार से प्रदूषण होता हैं। जो डोमेस्टिक वाटर वेस्ट हैं, उससे प्रदूषण होता हैं, जो इंडस्ट्रीयल वाटर होता हैं, उससे प्रदूषण होता हैं। यही नहीं इस तरह के नॉन प्वाइंट सोर्सेज भी होते हैं, जिनका हमें पता हीं नहीं चलता हैं, runoff from agricultural fields, dumpingof burnt and half-burnt bodies, जैसे अभी माननीय सदस्यों ने बताया हैं। इसके अलावा और बहुत सारे प्रदूषण के कारण हैं। अभी centarl pollution contol board ने सारे देश में पॉल्यूशन का आकलन किया हैं, 29 हजार एमएलडी, उन लोगों ने यह बताया हैं कि देश में यह पॉल्यूशन हैं चाहे वह नदियों से हो, चाहे वैट लैड्स हैं, चाहे झीलें हैं या ऐसी नदियां हैं जो पेरिनियल हैं, नॉन पेरिनियल हैं,लेकिन एक बहुत बड़ा मेग्नीट्यूड हैं, एक बहुत बड़ी समस्या हैं। इसको हैडल करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स की जरूरत हैं। सर, पानी स्टेट सब्जेक्ट हैं। इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट कंकरेंट सूची में हैं। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं,केन्द्र सरकार हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, अर्बन बॉडीज हैं और जनरल पब्लिक हैं, इन सबके सहयोग से ही इस समस्या का हल पाया जा सकता हैं। भारत में सबसे पहले 1985 में राजीव जी ने गंगा एक्शनप प्लान फेज-1 प्रांरभ किया, जो सन् 2000 में कम्पलीट हुआ। गंगा एक्शन प्लान फेज-21995 में प्रारम्भ किया गया और उसमें भी यमुना फेज-1 1993 में चालू हो गया।

इस magnitude को देखकर भारत सरकार ने 1995 में एक decision लिया कि इन सारी नदियों की सफाई के काम को National River Conservation Plan के तहत ले लिया जाए। आज की तारीख में सारे देश में इसी प्लान के तहत नदियों का conservation चल रहा हैं। इसमें Ganga Action PlanII की 5 नदियां हैं। और 29 दूसरी नदियां हैं। इस प्रकार आज देश में 34 नदियों में conservation का काम चल रहा हैं,160 TOWN मे ये schemes दी गई हैं और 20 राज्यों में इनका कार्य चल रहा हैं। इसके लिए हमारी जो approved cost हैं, वह 4,735 करोड़ रूपए की हैं। इसमें funding pattern भी हैं- आज की तारीख में 70 प्रतिशत Government of india दे रही हैं और 30 परसेंट स्टेट्स देती हैं। पहले Action Plan, Phase 1100 परसेंट भी चला हैं, फिर 1997 में50:50 हुआ, आज यह 70:30 चल रहा हैं। हम Japan Bank of International Cooperation से soft loan ले रहे हैं, वह 85:15 पर चल रहा हैं।

उपसभापति जी, यह हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या हैं। आज हमारे देश में Natinal River Conservation Plan के तहत 932 schemes चल रही हैं, जिनमे से 570 पूरी हो चुकी हैं। अभी 5,364 MLD को handle करने का प्रोग्राम हमने बनाया हैं,जिसकी approved cost 4,735 करोड़ रूपए की हैं इसको पूरा करने के लिए हमारे पास अभी तक 10th plan को जो fund allocation है, उसमें भी हमें 1,672 करोड़ रूपए की कमी पड़ रही है। गंगा और यमुना की बात अभी यहां हो रही थी। गंगा में first phase, वर्ष 2000 में complrtr हुआ, अभी इसका second phase चल रहा हैं। इसी तरह यमुना का first phase वर्ष 2003 में पूरा हो गया था। आज भी गंगा और यमुना का जो pollution load है, उसको handle करने के लिए 3,064 करोड़ रूपए कि आवश्यकता हैं। हमारे रूड़की के इंस्टीट्यूट ने हमारे पास कुछ और नदियों के pollution की रिपोर्ट भेजी हैं, उसके लिए भी पैसे चाहिए। कहने का मतलब यह हैं कि आज जितनी हमारी approved cost हैं और जो pollution load है, आज की तारीख में इन सबको handle करने के लिए 7,358 करोड़ रूपए की requirement हैं। अभी गंगा की बात आई। Central Pollution Control Board ने, 1985 में जब गंगा नदी में pollution load आंका था, तो वह 1,340 MLD था। उस वक्त हमारे पास पैसे की कमी थी। उस समय 882 MLDload के लिए यानी 65 परसेंट load के लिए ही पैसा sanction किया गया था। उसके पूरा हो जाने के बाद, आज की तारीख में 2,538 MLD और में 780 MLDhandle करने के बाद भी , 876 MLD फिर भी रह जाएगा। कहने का मतलब यह हैं कि गंगा के पूरे pollution land को समाप्त करने के लिए, आज कें हिसाब से 1,300 करोड़ रूपए की आवश्यकता होगी।

उपसभापति जी, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही हैं, आज गंगा के बेसिन पर और उसकी tributaries पर 40 से 50 करोड़ आबादी, upstream area में रहती हैं। यह खाली गंगा का सवाल नहीं हैं, यह उसमें मिलने वाली नदियों का भी सवाल हैं। वहां से भी pollution आ रहा हैं। इन सबको treat करने की आवश्यकता होगी। इतने बड़ें भारी क्षेंत्र में जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही हैं और वहां से जो pollution load आ रहा है, जो म्युनिसिपल सीवेज आ रहा हैं, उसको handle करने के लिए हमें capacity develop करनी हैं। माननीय सदस्यों ने बिल्कुल वाजिब कहा कि आपने बहुत सारे capacity sewage treatment plants बना दिए हैं। भारत सरकार, राज्यों सरकारों को और म्युनिसिपल बॉडीज को supplement करती हैं, support करती हैं, वह टाइम। जो भी facilites create हो जाती हैं, उनकी runnig और उनकी maintenance कि जिम्मेंदारी स्टेट गवर्नमेट की होती हैं। मैं कई सदस्यों से सहमत हूं, जिन्होने बताया कि faclity create हो गई, लेकिन उसके बाद उसको चलाया नहीं गया। इसमें सबसे बड़ा जो defaulter हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी हैं, वे यूपी सरकार को तीन चिट्ठी लिख चुके हैं -2004 में लिखी, 2 जून 2005 में। उन्होने यहीं कहा हैं कि आपकी जो facilites create हो गई हैं, उनको maintain कीजिएगा, उनको बिजली दीजिएगा और उनको चलाइए, अन्यथा अगर ये facilites create हो गई और अगर untreated water नदियों में जाएगा, तो facility create करने से क्या हुआ। मुझे अभी आधिकारियों से जानकारी मिली है कि इस साल यूपी ने अपने बजट में भी इस चीज के लिए पैसा रखा हैं। कई स्टेट्स ने अच्छा काम किया हैं। उत्तराचंत ने जो facilites create हुई हैं, उनका फायदा उठाया हैं, पानी शुद्ध हुआ हैं। हरियाणा में जो facilites create हुई हैं, उससे यमुना का पानी अच्छा हुआ हैं। वेस्ट बंगाल ने बहुत अच्छा काम किया हैं। कहने का मतलब यह हैं कि सारे stakeholders को चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे म्युनिसिपैलिटीज हों, सबको मिल कर काम करना पड़ेगा। पब्लिक में geneal awareness भी लानी पड़ेगी, सब लोगो में लानी पड़ेगी ताकि नदियों का पानी दूषित नहीं हो।

सर, मैं बिना संकोच यह भी बताऊंगा कि वाराणसी की बात आई। वाराणसी में अभी गंगा का sevond phase चल रहा हैं, उसके अंदर 160 कस्बों को इसमें लिया गया हैं,जिसमें वाराणसी भी हैं। उत्तर प्रदेश में सेंकड फेज में भी वाराणसी में काम चल रहा हैं। Japan Bank of International Co operation से वाराणसी के लिए 552 करोड़ का soft loan लिया जा रहा हैं। इसके लिए भारत सरकार के साथ agreement हो गया हैं। DPRs कुछ आ गई हैं, कुछ आ रही हैं।process मे चल रही है अभी इसके cabinet approval की कारवाई चल रही है मेरा ऐसा मानना हैं कि यह स्कीम जितनी लागू हो जाएगी, इस financial year के end तक हो जाएगी, तो वाराणसी का जो leve। है, वह और बढ़िया होगा।

काम चल रहा हैं। महोदय मेरा यह मानना हैं कि फेज 2 से गंगा और बेहतर होगी और दो-तीन तरह के लोन वाराणसी, कानपूर, इलाहाबाद और लखनऊ के लिए आ रहे हैं। यह सारी कार्यवाही मंत्रालय से हो चुका हैं। तो मेरा मानना हैं कि इस सब में हम गंगा के पानी को और बेहतर बना सकेंगे।

महोदय, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। मैंने बीच में उस दिन भी सवाल का जवाब दिया था कि फंड्स की जरूरत हैं। हम ने दो साल में 75 करोड़ रूपए गंगा फेज 2 में दिए हैं और पिछले 6 साल में, अभी हमारे उधर के भाई नहीं बैठे ....(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश) **:** हम आप को बैठे दिखायी नहीं दे रहे?

श्री नमो नारायण मीणा : उन्होने 6 साल में 222 करोड़ ही दिए थे। यह प्रोग्राम राजीव गांधी जी ने चलाया और हम ने ज्यादा फंड्स दिए हैं। हम आगे भी गंगा के पानी को शुद्ध करने के लिए और भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस के लिए लोन ला रहे हैं और सब की मदद से काम कर रहे हैं। कुछ स्टेट्स की वजह से गड़बड़ी हो रही हैं। मैंने आप को यू.पी. के बारे में बताया कि वहां से मेंटेनेंस और दूसरी चीजें नहीं हो रही हैं। अगर वे सब होंगी तो मेरा मानना हैं कि गंगा शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, इसे हम भी चाहते हैं और सारा देश चाहता हैं। महोदय, यह राजीव जी का सपना था जिस पर यू.पी.ए. की इस सरकार में और डा. मनमोहन जी के नेतृत्व में और ज्यादा कार्य होगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं।,

श्री कमाल अख्तर : सर, एक सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं। ऐसा लगता हैं कि मंत्री जी ने चर्चा का जवाब नहीं दिया, यू.पी.ए. और राजीव जी के सपने के बारे में सदन को अवगत कराया। सर, मैंने अपने क्वैश्चन के अंदर जुबिलिएंट ऑर्गेनिक्स, गजरौला का जिक्र किया था जहां से गंगा की शुरूआत होती हैं। उस में जस्टिस घुम्मल मल लोढ़ा की 17 सदस्यीय समिति बनी।

इसकी रिपोर्ट मंत्रालय के पास हैं। जब कोई गंम्भीर समस्या हैं, जहां लाखों लोगों की जान का खतरा हैं, तो मंत्री जी या सरकार कितने दबाव में हैं, यह मंत्री जी के स्टेटमेंट से जाहिर हो गया कि उन्होने एक बार भी ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : वे जवाब दे रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री कमाल अख्तर :सर, सर एक मिनट ...(**व्यवधान**)... मेरी बात पूरी होने दीजिए, सर। मेरा क्वैश्चन पूरा होने दीजिए। मंत्री जी बाद में जवाब दे देंगे, मेरा क्वैश्चन पूरा होने दीजिए, सर।

मंत्री जी कितने दबाव में हैं, यह इस बात से जाहि होता हैं कि एक क्वैश्चन पर उन्होने एक बार भी ऐसी किसी भी जांच का नाम नहीं लिया कि हम यह जांच कराने को तैयार है। हम लोगों ने मांग की हैं कि आपका और राजीव जी का सपना गंगा को साफ कराने का हैं, अगर आप

सर, माननीय सदस्य ने एक controversy के बारे में बताया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेट गवर्नमेंट जो प्रस्ताव भेजती हैं,हम उनको मंजूरी देते हैं। उनके जल निगम और स्थानीय म्युनिसिपैलिटी के बीच आपस में कुछ मामला था, वह सुप्रीम कोर्ट में भी गया। वह वहीं कहीं 5-6 साल का अटक गया। लेकिन उनकी 41 करोड़ के आसपास की जो स्कीमें थीं, वे चालू हो गई हैं, उनसे भी improvement होगा। भारत सरकार के पास स्टेट गवर्नमेंट जो प्रस्ताव बनाकर भेजती हैं, हम उनकी मंजूरी करते हैं और हमने इनको मंजूरी दे दी हैं,loan agreement sign हो गया हैं। इससे स्थिति ठीक होगी।

सर, गंगा phase- मे जो achievament हुई हैं, उनके बारे में एक perception हो गया हैं कि नदियों का जल सही नहीं हो पा रहा हैं। उसके अंदर कुछ न कुछ गड़गड़ी हैं।

उस के अंदर कुछ-न-कुछ गड़बड़ी हैं। मैं माननीय सदस्यों को एक बात से अवगत कराना चाहता हूं हमारे मंत्रालय का mandate bathing quality है। Drinking के लिए तो आप को साफ करना पड़ेगा।

महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि गंगा के बारे मे हमारे चार रेपूटेड इंस्टीट्यूशन हैं-सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, आई.आई.टी.कानपुर, लखनऊ की संस्था रिसर्च सेंटर और बी.एच.ई.एल. ये रेपटेड इंस्टीट्यूशन वाटर की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। हम ने गंगा के ऊपर 27 मॉनीटरिंग स्टेंशंस लगा रखे हैं जो वाटर क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। उन की रिपोर्ट के आधार पर ऋषिकेश से कन्नौज अपर-स्ट्रीम तक वाटर क्वालिटी बी.ओ. और बी.ओ.डी. हैं। उन की बी.ओं. और बी.ओ.डी. में 1986 के फिगर्स के बाद 2005 के फिगर्स में इम्प्रूवमेंट दिखाई देती हैं। इसी प्रकार इलाहाबाद डाउन स्ट्रीम में भी 86 के मुकाबले इम्प्रूवमेंट हैं, लेकिन फिर भी डिजायर्ड जितना होना चाहिए, उस से कम हैं, सुधार की गुंजाइश हैं। इन के कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ व वाराणसी के लिए तो एग्रीमेंट हो चुका हैं। हमारी सरकार ने जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन से इलाहाबाद कानपुर और लखनऊ के लिए 1100 करोड़ रूपए का और उन के सामने पोज किया हैं ताकि उन से एग्रीमेंट होकर और सोफ्ट लोन मिले। इलाहाबसद, कानपुर और लखनऊ की समस्या इस से और अच्छी तरह हल होगी।

महोदय, हमारी सरकार इस संबंध में पूरा भरसक प्रयास कर रही हैं। यह राजीव जी का सपना था कि गंगा नदी साफ हो। उस में पहले फेज में इम्प्रूवमेंट हुआ हैं। दूसरे में 100 कस्बों में काम चालू हो गया हैं। उत्तर प्रदेश मे गंगा के कोर्स में 13 स्कीइम्स सेंक्शंड हो चुकी हैं, उत्तरांचल में 37, झारखंड में 2, बिहार में 18, बंगाल में 165 और कोलकत्ता में टेनरीज के लिए तीन स्कीम्स हैं। इस तरह फेज 2 में कुल 268 स्कीम्स गंगा फेज 2 में सेंक्शंड कर दी गयी हैं। इस पर

राजीव जी के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो पूरा करिए, लेकिन कम-से-कम उन संस्थाओं के खिलाफ, जो गंगा को, राजीव जी के सपने को खराब कर रहे हैं, उन संस्थाओं क खिलाफ कोई जांच की घोषणा आप करें, तो हम मानेंगे कि वाकई आप लोग गम्भीर हैं और राजीव जी का सपना पूरा करना चाहते हैं।

श्री नमो नारायण मीणा : सर, माननीय सदस्य को जो मैंने स्टेटमेंट दिया हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री कमाल अख्तर : यह गलत है सर, यह रौंग हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल वहीं हैं, जो मैनेजमेंट द्वारा केन्द्रीय मंत्रालय और केन्द्रीय बोर्ड को लिख कर दिया गया हैं। यह वही स्टेटमेंट हैं। मैं इस सदन के अन्दर कहता हूं और मैं आज भी इतनी बड़ी बात कह कर जा रहा कि आप संसदीय समिति की टीम भेज दीजिए या उच्च स्तरीय जांच करा लीजिए, अगर वहां पर यह नहीं पाया गया, जो कि इन्होने लिखा हैं कि यह बारहमासी नहीं हैं, लेकिन आज भी आप जाकर देख लीजिए कि वहां पर पानी बहता हैं।आप आज भी जाकर देख लीजिए कछला घाट पर बगद नदी गिरती हैं। वह बहुत महत्वपूर्ण नदी ळैं। मैं वहां पैदा हुआ और जहां तक मैं जानता हूं कि वहां के ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में केन्द्रीय बोर्ड की समीक्षा बिल्कूल फर्जी हैं और सिर्फ असत्य हैं।केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के अधिकारयों ने वहां से भारी मात्रा में पैसा लेकर मंत्रालय को यह रिपोर्ट भेज दी हैं। मेंरा आपके माध्यम से मंत्री जी से फिर अनुरोध हैं कि अगर आप राजीव जी का सपना पूरा करना चाहते हैं, आप वकाई समर्पित हैं,तो केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड से अलग कोई जांच समिति बने या घुम्मन मल लोढ़ा जी की समिति की रिपोर्ट निकलवा कर दोबारा टेबल करा दीजिए। जस्टिस घुम्मन मल लोढ़ा जी की जो समिति बनी है, उसी तरह की एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति बनाकर वहां पर जाचं करोई जाए। वहां के जो लाखों करोड़ो लोग बरबाद हो गए और वहां आने वाले समय में जो भोपाल जैसी पुनरावृत्ति होने वाली हैं, उसके लिए उस जनता के लिए आप जवाब दें, तो ज्यादा बढिया होगा।

श्री नमो नारायण मीणा : सर, मैंने माननीय सदस्य को अपने स्टेटमेंट में, जो आपने मैसर्स जुबिलिएन्ट आर्गेनिक्स लिमिटेड, गजरौला और वहां और जो दूसरी यूनिट्स हैं तथा और जिन्होने काम किया हैं, उसके संबंध में प्रश्न उठाया था,तो हमारी ओर से गंगा नदी को प्रदूषित करने वाली कुल 187 उघोगों की बात की गई,जिनमें से 112 उघोगों में effluent treatments plant लगाए गए हैं, जो कार्य कर रहे हैं और हमने 75 उघोगों को बन्द कर दिया हैं।

इसी प्रकार माननीय सदस्य जिसको रेफर कर रहे हैं, मैसर्स जुबिलिएन्ट आर्गेनिक्स लिमिटेड गजरौला का, तो केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार जो सवाल थे कि वह नदी बारहमासी नहीं हैं। उसमें किसी प्रकार का औघोगिक बहिस्राव, पॉल्युशन का निस्तारण नहीं होता हैं। अगर माननीय सदस्य को किसी प्रकार की कोई कम्प्लेट हैं, कोई किसी तरह की बात हैं, तो आप बता रहे हैं, उसको मैं देख लूंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री कमाल अख्तर : सर, सदन में यह मामला उठा हैं। यह हम भी जानते हें कि कोई कम्प्लेंट हमने मंत्री जी को लिख कर दिया, तो उनका जवाब आ जाता हैं कि हम देख रहे है? अगर सदन में मामला उटा हैं,तो मंत्री जी को घोषण करनी चाहिए कि कौन सी उच्च स्तरीय समिति से वहां की जांच करा रहे हैं? कौन-सी पार्लियामेंटरी ज्वायंट एक्शन कमेटी बनाकर दोबार जांच करा रहे हैं? तब तो इसका कार्य सार्थक हैं, तभी राजीव जी का सपना पूरा हो रहा हैं, नहीं तो बातों राजीव जी का सपना पूरा नहीं हो रहा हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The discussion is over. The House is adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

The House then adjourned at fourteen minutes past eight of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 23rd May 2006.